दृष्टि The Vision

करेंट अफेयर्स झारखंड

दिसंबर 2021

(संग्रह)

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

फोन: 8750187501

ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

झारखंड **5**

- बीएसएल को मिला ग्रीनटेक एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी अवॉर्ड 5
- बीएसएफ का 57वाँ स्थापना दिवस 5
- 'प्रोजेक्ट कवच' 6
- 'हमार अपना बजट' पोर्टल और मोबाइल ऐप 6
- झारखंड ने जीती दिव्यांग क्रिकेट सीरीज़ 7
- लोयोला स्कूल देश के टॉप 100 में 7
- सीसीएल और झारखंड चिड़ियाघर प्राधिकरण के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर 7
- मुख्यमंत्री ने चार कपड़ा उद्योगों का उद्घाटन किया 8
- डालमिया भारत सीमेंट संयंत्र का विस्तारीकरण 8
- 'आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम 9
- रिम्स की दूसरी कैथलैब शुरू 9
- राज्य का पहला ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट 10

नोट :

- झारखंड एकेडमिक काउंसिल को मिला चेयरमैन 10
- प्रसिद्ध रजरप्पा मंदिर में बलि चढ़े बकरों से बनेगी बिजली 11
- 'आपके अधिकार-आपकी सरकार आपके द्वार' 11
- नान कम्युनिकेबल डिजीज स्क्रीनिंग (एनसीडी स्क्रीनिंग) 12
- झारखंड उच्च न्यायालय की कार्यवाही का सीधा प्रसारण 13
- आजीविका उन्नयन हेतु तसर फार्मिंग की होगी शुरुआत 13
- 'SAHAY' योजना 13
- मुख्यमंत्री ने Safe and Responsible Migration Initiative (SRMI) का किया शुभारंभ 14
- ICJS अवार्ड में झारखंड पुलिस की CCTNS को देश में मिला तीसरा स्थान 15
- उदयन माने बने पीजीटीआई ऑर्डर ऑफ मेरिट चौंपियन 15
- स्कॉच पुरस्कार 15
- 'उड़ान 2021' क्विज के विजेता बने जयकांतन आर 16
- टाटा स्टील को मिला 'सुरक्षा और स्वास्थ्य मान्यता 2021' 16
- विधानसभा में 2926.12 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पारित 17
- ग्लोबल पीटर ड्रकर चैलेंज 17
- गरिमा परियोजना अंतर्गत डायन कुप्रथा मुक्त झारखंड के लिये कार्यशाला आयोजित 17

नोट :

- बिरसा मुंडा संगीत और नृत्य महोत्सव 18
- एकीकृत कृषि क्लस्टर 18
- सुशासन सूचकांक, 2021 में झारखंड 19
- मुख्यमंत्री आमंत्रण राज्यस्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता-2021 का समापन 20
- नीति आयोग स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में झारखंड 20
- 'बिरसा हरित ग्राम योजना' पर आधारित प्रशिक्षण पुस्तिका का विमोचन 21
- सरकार की दूसरी वर्षगाँठ के अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों को दी कई सौगातें 21
- IIT-ISM और डसॉल्ट ने खनन और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिये MoU पर हस्ताक्षर किये 22

The Vision

नोट :

झारखंड

बीएसएल को मिला ग्रीनटेक एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी अवॉर्ड

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में झारखंड के बोकारो स्टील प्लांट को 21वाँ वार्षिक ग्रीनटेक पर्यावरण पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

प्रमुख बिंदु

- बीएसएल को यह पुरस्कार महाबलीपुरम् में आयोजित '21वें वार्षिक ग्रीनटेक पर्यावरण शिखर सम्मेलन' के दौरान प्रदान किया गया था।
- मुख्य महाप्रबंधक (COBPP) राकेश कुमार और एन.पी. श्रीवास्तव ने बीएसएल की ओर से महाबलीपुरम् में पुरस्कार प्राप्त किया।
- उल्लेखनीय है कि बीएसएल ने प्रभारी निदेशक अमरेंदु प्रकाश के नेतृत्व में कचरे को धन में बदलने का अभियान चलाया है और पिछले कुछ वर्षों में कचरे के उचित उपयोग और इसके उपयोग से 1,000 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व अर्जित किया है।
- इस अवसर पर एन.पी. श्रीवास्तव को पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उनके योगदान के लिये व्यक्तिगत श्रेणी में महाबलीपुरम् में ग्रीनटेक पर्यावरण नेता पुरस्कार भी मिला।
- ग्रीनटेक एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी अवॉर्ड्स स्थायी लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में ज़िम्मेदार, नवीन प्रथाओं और पहल को मान्यता प्रदान करने के लिये प्रस्तुत किये जाते हैं।

बीएसएफ का 57वाँ स्थापना दिवस

चर्चा में क्यों ?

- 1 दिसंबर, 2021 को झारखंड के हज़ारीबाग में भारतीय सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र और स्कूल मेरु कैंप ने बीएसएफ का 57वाँ स्थापना दिवस मनाया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर राज्यपाल रमेश बैस ने मुख्य अतिथि के रूप में समारोह का उद्घाटन किया और प्रशिक्षण शिविर के परिसर का अवलोकन किया।
- राज्यपाल ने कहा कि यह सभी के लिये गर्व की बात है कि सीमा सुरक्षा बल 1 दिसंबर, 1965 से अर्धसैनिक बल के रूप में देश की सेवा में लगातार काम कर रहा है। श्री के एफ रूस्तमजी इसके पहले प्रमुख और संस्थापक थे। श्री पंकज कुमार सिंह वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक हैं
- 1965 में कुल 25 बटालियन के साथ सीमा सुरक्षा बल का गठन हुआ था और समय के साथ पंजाब, जम्मू व कश्मीर, नार्थ-ईस्ट में आतंकवाद की रोकथाम के लिये सीमा सुरक्षा बल का विस्तार होता रहा ।
- वर्तमान समय में सीमा सुरक्षा बल की 192 बटालियन (3 एन.डी.आर.एफ बटालियन सहित) और 7 आर्टी रेजिमेंट भारत- पाकिस्तान और भारत-बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा में तैनात हैं।
- इसके अतिरिक्त सीमा सुरक्षा बल कश्मीर घाटी में घुसपैठ, नार्थ-ईस्ट क्षेत्र में आंतरिक सुरक्षा, ओडिशा एवं छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान और भारत-पाकिस्तान एवं भारत-बंग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एकीकृत जाँच चौकी में तैनात है।

नोट :

'प्रोजेक्ट कवच'

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में झारखंड में स्थित बोकारो स्टील प्लांट (बीएसएल) के प्रबंधन ने प्लांट स्तर पर सुरक्षा प्रदर्शन में सुधार के उद्देश्य से सुरक्षा संस्कृति में परिवर्तन के लिये 'प्रोजेक्ट कवच' लॉन्च किया है।

प्रमुख बिंदु

- बीएसएल ने 'सुरक्षा सांस्कृतिक परिवर्तन' को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिये एक रोड मैप की सुविधा, संचालन और प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु एक प्रतिष्ठित सुरक्षा सलाहकार 'एएसके-ईएचएस इंजीनियरिंग एंड कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड' नियुक्त किया है।
- इस प्रमुख सुरक्षा पहल सह सांस्कृतिक अभियान को बीएसएल द्वारा 'परियोजना कवच' नाम दिया गया है।
- प्रोजेक्ट कवच का संपूर्ण उद्देश्य सभी कर्मचारियों और अनुबंध कर्मचारियों द्वारा सुरक्षित व्यवहार के माध्यम से कार्यस्थल के खतरों को कम करना है। कार्यस्थल पर खतरों और जोखिमों के खिलाफ सुरक्षित व्यवहार सबसे प्रभावी 'कवच' है।
- बोकारो इस्पात कारखाना सार्वजनिक क्षेत्र में चौथा इस्पात कारखाना है। यह सोवियत संघ के सहयोग से 1965 में प्रारंभ हुआ था।
- आरंभ में इसे 29 जनवरी, 1964 को एक लिमिटेड कंपनी के तौर पर निगमित किया गया और बाद में सेल के साथ इसका विलय हुआ। पहले यह सेल की एक सहायक कंपनी और बाद में सार्वजनिक क्षेत्र लोहा और इस्पात कंपनियाँ (पुनर्गठन एवं विविध प्रावधान) अधिनियम, 1978 के अंतर्गत एक यूनिट बनाई गई। कारखाने का निर्माण कार्य 6 अप्रैल, 1968 को प्रारंभ हुआ।
- यह कारखाना देश के पहले स्वदेशी इस्पात कारखाने के नाम से विख्यात है। इसमें अधिकतर उपकरण, साज-सामान तथा तकनीकी कौशल स्वदेशी ही हैं।
- कारखाने का 17 लाख टन इस्पात पिंड का प्रथम चरण 2 अक्टूबर, 1972 को पहली धमन भट्ठी चालू होने के साथ ही शुरू हुआ तथा निर्माण कार्य तीसरी धमन भट्ठी चालू होने पर 26 फरवरी, 1978 को पूरा हो गया।
- 40 लाख टन चरण की सभी यूनिटें चालू हो चुकी हैं और 1990 के दशक में आधुनिकीकरण से कारखाने की क्षमता बढ़ाकर 45 लाख टन तरल इस्पात की कर दी गई है।

'हमार अपना बजट' पोर्टल और मोबाइल ऐप

चर्चा में क्यों ?

- 2 दिसंबर, 2021 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री आवास कार्यालय से वित्त विभाग द्वारा तैयार हमार 'अपना बजट पोर्टल' और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- इस पोर्टल के माध्यम से राज्य की आम जनता 2022-23 के बजट के लिये अपने बहुमूल्य सुझाव साझा कर सकेगी।
- सरकार को सुझाव देने के लिये https://finance.jharkhand.gov.in/budgetvichar पर लॉग इन करना होगा और 'हमार अपना बजट पोर्टल' पर अपना पंजीकरण कराना होगा।
- होम पेज पर दिये गए स्थान में अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल (वैकल्पिक) दर्ज करने के बाद ओटीपी जनरेट करने के लिये क्लिक करना होगा। ओटीपी को किसी की सुविधा के अनुसार किसी भी समय ई-मेल या मोबाइल द्वारा ऑर्डर किया जा सकता है। मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी और उसके स्थान पर दिखाए गए कैप्चा कोड को दर्ज करने के बाद एक पंजीकरण पृष्ठ में प्रवेश किया जा सकेगा।

नोट :

झारखंड ने जीती दिव्यांग क्रिकेट सीरीज़

चर्चा में क्यों ?

- 3 दिसंबर, 2021 को विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर झारखंड दिव्यांग क्रिकेट टीम ने राष्ट्रीय दिव्यांग त्रिकोणीय टी20 क्रिकेट सीरीज़ का खिताब जीता।

प्रमुख बिंदु

- 3 दिसंबर, 2021 को इस सीरीज़ का फाइनल मुकाबला बिहार और झारखंड के बीच पटना के ऊर्जा स्टेडियम में खेला गया, जिसमें झारखंड की टीम ने बिहार को हराकर खिताब पर कब्ज़ा किया।
- इस मैच में वागीश त्रिपाठी को 'मैन ऑफ द मैच'घोषित किया गया तथा 'मैन ऑफ द सीरीज़'सौराष्ट्र के राजू परमकर को दिया गया।
- सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज़ का पुरस्कार झारखंड के वागीश त्रिपाठी और झारखंड टीम के ही निशांत कुमार उपाध्याय को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़ का पुरस्कार दिया गया।
- समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष मुकेश कंचन मौजूद थे।
- विदित हो कि इस सीरीज़ का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर बिहार दिव्यांग क्रिकेट संघ के द्वारा बिहार, झारखंड और सौराष्ट्र की टीम के बीच किया गया था।

लोयोला स्कूल देश के टॉप 100 में

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में प्रमुख शिक्षा समाचार पत्रिका द्वारा किये गए एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में, एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया, लोयोला स्कूल, जमशेदपुर को देश के शीर्ष 100 स्कूलों में स्थान दिया गया है।

प्रमुख बिंदु

- सर्वेक्षण वार्षिक एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग (EWISR) 2021-22 के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया था। टॉप 100 की लिस्ट में लोयोला ने 87वां रैंक हासिल किया है।
- सर्वेक्षण विभिन्न मानकों पर किया गया, जिसमें अकादमिक प्रतिष्ठा, सह-पाठ्यचर्या शिक्षा, खेल शिक्षा, शिक्षकों की गुणवत्ता, शिक्षक-छात्र अनुपात, नेतृत्व की गुणवत्ता, माता-पिता की भागीदारी, बुनियादी ढाँचा, पूर्व छात्रों की गुणवत्ता, अखंडता और चयन के लिये प्रतिष्ठा प्रवेश आसानी और पारदर्शिता शामिल है।
- 1947 में केवल 34 लड़कों के साथ शुरू हुआ लोयोला स्कूल, इस साल अपनी प्लेटिनम जुबली मना रहा है। स्कूल की स्थापना जनवरी 1947 में कोलकाता के दो जेसुइट्स, फादर सेसिल लीमिंग और फादर रॉबर्ट ड्रगमैन द्वारा की गई थी।

सीसीएल और झारखंड चिड़ियाघर प्राधिकरण के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

चर्चा में क्यों ?

- 4 दिसंबर, 2021 को झारखंड की राजधानी में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) और झारखंड चिड़ियाघर प्राधिकरण के बीच 36 लाख रुपए के समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये गए।

प्रमुख बिंदु

- एमओयू की शर्तों के तहत सीसीएल कंपनी की सीएसआर पहल के एक हिस्से के रूप में रांची के भगवान बिरसा बायोलॉजिकल पार्क में तीन साल के लिये शेरों और बाघों की एक जोड़ी को गोद लेगा। सीसीएल तीन साल तक पशुओं के रख-रखाव, भोजन और स्वास्थ्य से संबंधित सभी खर्चों को वहन करेगी।

नोट :

- जीएम (सीएसआर), सीसीएल, बाला कृष्णा लाडी और प्रधान मुख्य वन संरक्षक और निदेशक भगवान बिरसा जैविक उद्यान, जब्बर सिंह ने दोनों संगठनों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये।
- इस अवसर पर सीसीएल के सीएमडी, पीएम प्रसाद ने कहा कि कंपनी टिकाऊ खनन के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत के विजन को पूरा करने के लिये प्रतिबद्ध है।
- वन्यजीव संरक्षण पर्यावरण संरक्षण का एक महत्त्वपूर्ण पहलू है। जानवरों को गोद लेने से जानवरों के संरक्षण के महत्त्व के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने में मदद मिलेगी।
- सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड का मुख्यालय दरभंगा हाउस, रांची में है, जो महारत्न कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों में से एक है। झारखंड के आठ ज़िलों में इसकी परिचालन खदानें हैं। सीसीएल ने पर्यावरण संरक्षण और हितधारकों के समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिये विभिन्न पहल की हैं।

मुख्यमंत्री ने चार कपड़ा उद्योगों का उद्घाटन किया

चर्चा में क्यों ?

- 6 दिसंबर, 2021 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ओरमांझी (कुल्ही) स्थित चार कपड़ा उद्योग कंपनी किशोर एक्सपोर्ट्स, द बेस्ट बैंड, श्री गणपति क्रिएशन एवं वैलेंसिया अप्पेरल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने चंदवे-कुल्ही पथ का ऑनलाइन शिलान्यास भी किया।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की पॉलिसी है कि झारखंड में कार्यरत विभिन्न औद्योगिक संस्थाओं में 75% मानव बल झारखंड राज्य के हों, यह सुनिश्चित की जाए।
- टेक्सटाइल क्षेत्र में काम करने वाले 2,000 से अधिक लोगों में 95% लोग झारखंड के हैं, इसमें 80% महिलाएँ शामिल हैं। इन्हें मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र सौंपा। टेक्सटाइल क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी अधिक होने से महिला सशक्तीकरण को बल मिलेगा।
- नियुक्ति पत्र पाने वाली महिलाओं में वैसी भी युवतियाँ भी शामिल हैं, जो लॉककडाउन के पहले तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल जैसे राज्यों में काम कर रही थीं, राज्य सरकार ने उन्हें अपने गाँव-घर अथवा ज़िलों में ही रोज़गार देने का भरोसा दिया था।
- उद्योग सचिव पूजा सिंघल ने कहा कि बेहतर टेक्सटाइल पॉलिसी के तहत आने वाले 6 महीनों में टेक्सटाइल क्षेत्र में काम करने वाले 10 हज़ार लोगों को रोजगार मिलेगा इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है।

डालमिया भारत सीमेंट संयंत्र का विस्तारीकरण

चर्चा में क्यों ?

- 6 दिसंबर, 2021 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बोकारो के बालीडीह में डालमिया भारत सीमेंट संयंत्र की दूसरी इकाई (यूनिट- 2) का शिलान्यास किया।

प्रमुख बिंदु

- राज्य सरकार ने बोकारो ज़िले के बालीडीह इंडस्ट्रियल एरिया में डालमिया भारत सीमेंट संयंत्र विस्तारीकरण परियोजना के लिये 16 एकड़ ज़मीन उपलब्ध कराई है ।
- यहाँ पहले से स्थापित डालमिया भारत सीमेंट संयंत्र की उत्पादन क्षमता 3.7 मिलियन टन प्रति वर्ष है। नई इकाई के चालू होने पर वार्षिक उत्पादन क्षमता बढ़कर 6.2 मिलियन टन हो जाएगी। इसके लिये कंपनी 567 करोड़ रुपए का निवेश करेगी।
- राज्य सरकार की इस पहल से औद्योगिक विकास को मुकाम मिला है, नए संयंत्र से सैकड़ों लोगों को रोज़गार मिलेगा
- गौरतलब है कि झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति- 2021 के तहत इस वर्ष अगस्त में नई दिल्ली में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में आयोजित इन्वेस्टर्स समिट में डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड और उद्योग विभाग के बीच सीमेंट संयंत्र की स्थापना के लिये एमओयू हुआ था।

नोट :

'आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम

चर्चा में क्यों ?

- 7 दिसंबर, 2021 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहिबगंज ज़िले के बरहेट प्रखंड स्थित भोगनाडीह में 'आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार'कार्यक्रम में शामिल हुए।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वीर शहीद सिदो, कान्हू, चांद, भैरव और फूलो-झानो से संबंधित आर्ट गैलरी का उद्घाटन किया।
- मुख्यमंत्री ने गुमानी नदी के किनारे बनने वाले फूलो-झानो स्मृति वन का शिलान्यास किया। यहाँ फूलो-झानो की प्रतिमा लगाई जाएगी, वहीं इस स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में भी विकसित किया जाएगा।
- मुख्यमंत्री ने भोगनाडीह में खेलों को बढ़ावा देने के लिये क्रीड़ा किसलय फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया।
- उल्लेखनीय है कि घर-घर, जन-जन को सरकार का हिस्सा बनाने के मकसद से 'आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार'कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
- इस कार्यक्रम के तहत सभी पंचायतों में शिविर लगाकर सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। लोगों की समस्याओं का समाधान हो रहा है और उन्हें विकास योजनाओं से जोड़ा जा रहा है।
- मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 1296 योजनाओं का उद्घाटन-शिलान्यास किया। इनमें 1289 योजनाओं का शिलान्यास और 7 योजनाओं का उद्घाटन शामिल है।
- इसमें शिलान्यास की जाने वाली कुल योजनाओं में 1262 योजनाएँ जल जीवन मिशन से जुड़ी हैं। इसके अलावा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण करने के साथ नव चयनित कर्मियों को मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र प्रदान किया।

रिम्स की दूसरी कैथलैब शुरू

चर्चा में क्यों ?

- 8 दिसंबर, 2021 को रिम्स के सुपरस्पेशियलिटी कार्डियोलॉजी विभाग के एचओडी डॉ. हेमंत नारायण ने रिम्स की दूसरी कैथलैब का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- जीई कंपनी की यह कैथलैब ईस्ट इंडिया की पहली बाईप्लेन कैथलैब है।

अब इस एडवांस मशीन की शुरुआत होने से इसका फायदा हृदय रोगियों को मिलेगा। पहले कैथलैब होने के बावजूद वह अक्सर खराब पड़ी रहती थी। रोगियों की एंजियोग्राफी-एंजियोप्लास्टि और पेसमेकर लगाने का काम लटक जाता था। अब इस समस्या से निजात मिलेगी।

- गौरतलब है कि नवंबर 2021 में रिम्स में सिमंस कंपनी की सिंगल प्लेन कैथलैब की शुरुआत की गई थी।
- डॉ. हेमंत नारायण ने बताया कि रिम्स में कैथलैब की संख्या बढ़ने से मरीज़ों को अब समय पर ज़रूरी इलाज मिल सकेगा। इससे पहले ऑपरेशन के लिये मरीज़ों को लंबा इंतज़ार करना पड़ता था। अब पिछले दिनों की तुलना में तीन से चार गुना अधिक मरीज़ों का ऑपरेशन हो सकेगा।
- इस मशीन से गंभीर न्यूरोलॉजिकल ब्रेन से संबंधी बीमारियों का भी इलाज कम रेडिएशन में हो सकेगा। मशीन कम वक्त में बेहतर रिज़ल्ट दे पाएगी।

नोट :

राज्य का पहला ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में अग्रणी रियल एस्टेट कंपनी, समय कंस्ट्रक्शन प्रा. लिमिटेड ने झारखंड के आदित्यपुर में राज्य की पहली ग्रीनफील्ड परियोजना, सनराइज पॉइंट के लॉन्च करने की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- यह परियोजना आदित्यपुर के हरिओम नगर में स्थित है। यह एक अनुकरणीय आवासीय कॉलोनी है, जो एक एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है। इस परियोजनाओं को पूर्ण होने में 5 वर्ष का समय लगेगा।
- इस परियोजना की प्राथमिकताओं में निवासियों के आराम के साथ-साथ उनकी जीवन-शैली की गुणवत्ता में उत्कृष्टता के नए मानकों को डिज़ाइन किया गया है।
- इसमें विस्तृत खुले स्थानों को शामिल करने और मौजूदा पेड़ों को शामिल करने तथा नए पौधे लगाने का ध्यान रखा जाएगा, जिससे जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि, पर्यावरण पर प्रभाव को कम करने में मदद, वर्षा संचयन गड्ढे जल उपचार संयंत्र और उपचारित पानी के पुनर्चक्रण में मदद मिलेगी।
- इस परियोजना में 600 बहुमंजिला फ्लैट शामिल हैं, जो दो चरणों में पूरे होंगे। पहले चरण में 2 बीएचके और 3 बीएचके फ्लैटों के साथ-साथ ईडब्ल्यूएस फ्लैटों वाले 408 फ्लैटों का निर्माण किया जा रहा है।
- परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह बिष्टुपुर के बहुत करीब है तथा यहाँ से पीएम मॉल, रेलवे स्टेशन, अस्पताल, स्कूल कार्यालय सभी नज़दीक स्थित हैं।
- इसमें एम्फीथिएटर, गार्डन, पोडियम गार्डन, क्लब हाउस, जिम, मेडिटेशन हॉल, बैडमिंटन कोर्ट, शॉपिंग, सीसीटीवी, एलपीजी, जुस्को पावर जैसी सभी आधुनिक सुविधाएँ होंगी। बागवानी, कार धोने, शौचालय फ्लशिंग और अन्य के लिये फिल्टरिंग हेतु एसटीपी पानी का उपयोग करने की भी योजना है। यहाँ की सभी कॉमन लाइटें सोलर लाइट होंगी।
- परियोजना के प्रस्तावकों द्वारा परियोजना स्थल से सटी सड़क के किनारे हरित पटी का निर्माण किया जाएगा, जिसका परिवेश पर समग्र शीतलन प्रभाव पड़ेगा।

झारखंड एकेडमिक काउंसिल को मिला चेयरमैन

चर्चा में क्यों ?

- 10 दिसंबर, 2021 को झारखंड के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने जानकारी दी कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नाम की घोषणा हो गई है।

प्रमुख बिंदु

- राँची यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक और बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी के प्रोवीसी रहे डॉ. अनिल महतो इसके अध्यक्ष होंगे, जबकि केसी कॉलेज बेडो के प्रोफेसर इंचार्ज डॉ. विनोद सिंह उपाध्यक्ष होंगे।
- डॉ. अनिल कुमार महता की नियुक्ति (JAC) के अध्यक्ष पद पर 3 वर्ष के लिये हुई है।
- शिक्षा मंत्री की अनुशंसा पर मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलते ही अधिसूचना जारी कर दी जाएगी, नियुक्ति के बाद मैट्रिक-इंटर की परीक्षाएँ समय पर और सुचारु हो पाएंगी।
- उल्लेखनीय है कि JAC के पूर्व अध्यक्ष अरविंद प्रसाद सिंह और उपाध्यक्ष फूल सिंह का कार्यकाल 14 सितंबर, 2021 को पूर्ण हो गया था।
- शिक्षा मंत्री ने बताया कि JAC अध्यक्ष पद के लिये तीन लोगों के नाम आए थे। इनमें डॉ. अनिल कुमार महतो, ऊषा किरण और डॉ. शब्बीर हुसैन शामिल थे। वहीं उपाध्यक्ष के लिये सिर्फ डॉ. विनोद सिंह का ही बायोडाटा मिला था।

नोट :

- गौरतलब है कि जैक में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पद रिक्त होने से 8वीं से लेकर मेडिकल-इंजीनियरिंग के एंट्रेस टेस्ट, छात्रवृति परीक्षा एवं कई महत्त्वपूर्ण परिणाम प्रभावित हो रहे थे।

प्रसिद्ध रजरप्पा मंदिर में बलि चढ़े बकरों से बनेगी बिजली

चर्चा में क्यों ?

- 12 दिसंबर, 2021 को झारखंड राज्य के रामगढ़ ज़िले की उपायुक्त माधवी मिश्रा ने ज़िले के प्रसिद्ध रजरप्पा के माँ छिन्नमस्तिका मंदिर में बलि चढ़ाए गए बकरों से बिजली बनाने की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- रजरप्पा के माँ छिन्नमस्तिका मंदिर में बलि चढ़े बकरों के बेकार हिस्सों का इस्तेमाल कर बिजली बनाने के लिये मंदिर परिसर में एक संयत्र लगाया जाएगा, जो एक वर्ष में काम करने लगेगा।
- उल्लेखनीय है कि भैरवी और दामोदर नदी के संगम पर स्थित रजरप्पा मंदिर देश-विदेश में एक सिद्धपीठ के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ श्रद्धालु मन्नत पूरी होने पर बकरे की बलि चढ़ाते हैं। रोज़ाना करीब 150 बकरों की बलि दी जाती है।
- सरकार मंदिर की सुविधाएँ विश्वस्तरीय बनाने में जुटी है। इसी के तहत यहाँ बकरों की बलि, चढ़ने वाले फूलों के प्रबंधन को लेकर नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी है।
- बिजली बनाने के लिये मंदिर परिसर में मिथिनेशन प्लांट लगाया जाएगा तथा एक सेमीऑटोमैटिक स्लॉटर हाउस और अरगबत्ती प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाई जाएगी। इन तीनों प्रोजेक्ट पर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट करीब 72 लाख रुपए खर्च करेगा।
- नई व्यवस्था में बकरे की बलि के साथ बलि चढ़ाने वाले को एक टोकन दिया जाएगा।
- अर्द्धस्वचालित स्लॉटर हाउस में बलि के बाद बकरे के बेकार हिस्सों को प्लांट में डालकर रोज़ 23 किलोवॉट बिजली बनाई जाएगी। इससे मंदिर परिसर में लगी स्ट्रीट लाइट जगमग रहेंगी।
- प्लांट की क्षमता प्रतिदिन एक टन अपशिष्ट इस्तेमाल करने की होगी। मंदिर से रोज़ औसतन 900 किलो अपशिष्ट निकलता है।

'आपके अधिकार-आपकी सरकार आपके द्वार'

चर्चा में क्यों ?

- 11 दिसंबर, 2021 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल हज़ारीबाग में आयोजित 'आपके अधिकार-आपकी सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमंडलस्तरीय मेगा परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम में 25 लाख 92 हज़ार 856 लाभुकों के बीच कुल 22 अरब 30 करोड़ 29 लाख 6 हज़ार रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया ।

प्रमुख बिंदु

- कार्यक्रम में उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले 7 ज़िलों- हज़ारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद तथा चतरा के लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया गया।
- इनमें हज़ारीबाग ज़िले के 5,68,312 लाभुकों के बीच 2 अरब 57 करोड़ 26 लाख 28 हज़ार रुपए, कोडरमा ज़िले के 58 हज़ार 990 लाभुकों के बीच 1 अरब 19 करोड़ 89 लाख 60 हज़ार रुपए, रामगढ़ ज़िले के 4 लाख 67 हज़ार 412 लाभुकों के बीच 1 अरब 97 करोड़ 51 लाख 67 हज़ार रुपए का वितरण किया गया।
- इसी प्रकार गिरिडीह ज़िले के 1 लाख 53 हज़ार 688 लाभुकों के बीच 5 अरब 98 करोड़ 82 लाख 55 हज़ार रुपए, बोकारो ज़िले के 63 हज़ार 625 लाभुकों के बीच 4 अरब 53 करोड़ 30 लाख 36 हज़ार रुपए, धनबाद ज़िले के 8 लाख 84 हज़ार 850 लाभुकों के बीच 2 अरब 34 करोड़ 89 लाख 55 हज़ार रुपए तथा चतरा ज़िले के 3 लाख 95 हज़ार 979 लाभुकों के बीच 3 अरब 68 करोड़ 69 लाख 5 हज़ार रुपए का वितरण किया गया।

नोट :

- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में 'आपके अधिकार-आपकी सरकार आपके द्वार' योजना से संबंधित पुस्तिका का विमोचन भी किया।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तक इस योजना के तहत 2 लाख 50 हज़ार शिकायत दर्ज कराई गई, जिनमें से 2 लाख 20 हज़ार शिकायतों का त्वरित निष्पादन किया जा चुका है।
- मरांग गोमके पारदेशीय शिक्षा योजना के तहत 6 आदिवासी विद्यार्थियों को विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिये भेजा गया था। अब सभी वर्ग इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
- मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के प्रत्येक गाँव के 60 साल से अधिक के बुजुर्गों को पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा। हर एक विधवा, बुजुर्ग, दिव्यांग असहाय को सरकार पेंशन देगी। राज्य में गंभीर बीमारी की चिकित्सा के लिये सरकार हर व्यक्ति, जिसकी आय 8 लाख से कम है, के इलाज में सहायता करेगी।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार विभिन्न बड़े उद्योगों को राज्य में स्थापित करने का कार्य कर रही है, जिससे यहाँ के लोगों को रोज़गार के अवसर प्राप्त हो सकें। इस क्रम में इस पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि इनमें 75% नौकरी एवं 1 करोड़ रुपए तक का टेंडर स्थानीय लोगों को ही प्राप्त हो, जिससे राज्य के लोगों का विकास हो।

नान कम्युनिकेबल डिजीज स्क्रीनिंग (एनसीडी स्क्रीनिंग)

चर्चा में क्यों ?

- 13 दिसंबर, 2021 को आज़ादी के अमृत महोत्सव कैंपेन तथा दिल्ली में आयोजित यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिवस पर नान कम्युनिकेबल डिजीज स्क्रीनिंग (एनसीडी स्क्रीनिंग) केटेगरी में झारखंड को देश में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है।

प्रमुख बिंदु

- एनसीडी स्क्रीनिंग केटेगरी में तीसरे स्थान का यह पुरस्कार केंद्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार के द्वारा प्रदान किया गया, जिसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अभियान निदेशक रमेश घोलप और स्टेट नोडल ऑफीसर एनसीडी डॉ. ललित रंजन पाठक ने अपनी टीम के साथ ग्रहण किया।
- इस समारोह में गुमला ज़िले के गम्हरिया स्थित आयुष्मान भारत-हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में कार्यरत टीम में शामिल सीएचओ अल्का खलखो, एएनएम बरेन मिंज और सहिया सालो देवी को उत्कृष्ट सेवा का पुरस्कार प्रदान किया गया।
- स्टेट नोडल ऑफीसर डॉ. एलआर पाठक ने बताया कि झारखंड में अब तक कुल 1633 आयुष्मान भारत-हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर संचालित हैं। राज्य के 1633 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान कुल 2,33,189 वयस्क व्यक्तियों की स्वास्थ्य जांच की गई। यह भारत सरकार द्वार निर्धारित लक्ष्य 1,61,900 से 71,289 अधिक है।
- इस दौरान सभी आयुष्मान भारत-हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर स्वास्थ्य संबंधी कुल 15,684 गतिविधियाँ की गई, जिनमें राज्य के कुल 4,45,853 लोगों ने भाग लिया।
- प्रति सेंटर 100 गैर-संचारी रोगों (नान कम्युनिकेबल डिजीज) की जांच और इलाज, प्रति सेंटर 10 वेलनेस एक्टिविटी (योगा सेशन, मॉर्निंग वॉक आदि) प्रमुख गतिविधियाँ तय की गई थीं।
- आयुष्मान भारत-हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के साथ गैर-संचारी रोगों की रोकथाम और इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर सभी स्वास्थ्य दिवस पर विशेष जाँच, योग एवं अन्य स्वास्थ्य सबंधी गतिविधियाँ कराई जा रही हैं।

नोट :

झारखंड उच्च न्यायालय की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

चर्चा में क्यों ?

- 14 दिसंबर, 2021 को झारखंड उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन के निर्देश पर उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल मोहम्मद शाकिर की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि ट्रायल के तौर पर वर्चुअल कोर्ट की कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- रजिस्टार जनरल के आदेश के अनुसार 15 दिसंबर, 2021 से उच्च न्यायालय की अदालती कार्यवाही का YouTube पर सीधा प्रसारण किया जाएगा।
- ऐसा करने वाला यह पटना उच्च न्यायालय के बाद देश का छठा उच्च न्यायालय होगा। इससे पहले गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पटना उच्च न्यायालय ने अदालती कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया है।
- इस दौरान सिर्फ कोर्ट नंबर 12 और कोर्ट नंबर 10 की अदालती कार्यवाही का यूट्यूब पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। जिस दिन कोर्ट वर्चुअल सुनवाई करेगी, उस दिन दोनों कोर्ट की कार्यवाही को कोई भी YouTube पर देखा जा सकता है।
- जिनको भी अदालत की कार्यवाही का सीधा प्रसारण देखना होगा, उन्हें झारखंड उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर जाना होगा जहाँ वे लाइव मेनू के ज़रिए कोर्ट की कार्यवाही को देख सकते हैं। इस दौरान न तो कोई इस पर कमेंट कर सकता है और न ही इस कार्यवाही को शेयर कर सकता है।
- रजिस्ट्रार जनरल मोहम्मद शकीर ने बताया कि अभी सिर्फ दो अदालतों की कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया जा रहा है। धीरे-धीरे उच्च न्यायालय की सभी अदालतों में ऐसी व्यवस्था कर दी जाएगी।

आजीविका उन्नयन हेतु तसर फार्मिंग की होगी शुरुआत

चर्चा में क्यों ?

- 15 दिसंबर, 2021 को झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग के सचिव मनीष रंजन ने बताया कि राज्य के आदिवासी बहुल क्षेत्र में आजीविका उन्नयन हेतु तसर आधारित आजीविका को बढ़ावा देने के लिये राज्य सरकार तसर फार्मिंग को योजना के रूप में लागू करेगी।

प्रमुख बिंदु

- मनीष रंजन ने कहा कि इस योजना के तहत ज़रूरतमंद परिवारों को लाभ मिल सके, इसके लिये लाभुकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही मनरेगा के अंतर्गत बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत पोषक पौधों के लिये वृक्षारोपण हेतु सुविधाएँ भी प्रदान करवाई जाएंगी।
- योजना की शुरुआत बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत प्रथम चरण में पाँच ज़िलों में 500-500 एकड़ में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में की जाएगी।
- इस संबंध में मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी. ने तसर विकास फाउंडेशन के पदाधिकारियों को तसर विकास के लिये व्यापक योजना बनाने एवं विशेषज्ञों व सिविल सोसायटी के साथ मिलकर एक राज्यस्तरीय कार्यशाला का आयोजन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

'SAHAY' योजना

चर्चा में क्यों ?

- 15 दिसंबर, 2021 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खेल और खेल प्रतिभा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कोल्हान की धरा से 'SAHAY' (Sports Action Towards Harnessing Aspiration of Youths) योजना का शुभारंभ किया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- इस योजना का संचालन खेल विभाग द्वारा किया जाएगा। योजना का उद्देश्य खेल के माध्यम से नक्सल प्रभावित क्षेत्र के युवाओं के हुनर को एक पहचान देकर सकारात्मक जीवन की ओर प्रेरित करना है।
- योजना के ज़रिये प्रथम चरण में नक्सल प्रभावित चाईबासा, सरायकेला-खरसावां, खूंटी, गुमला एवं सिमडेगा ज़िले के 14 से 19 वर्ष के 72 हज़ार युवक-युवतियों को खेल के क्षेत्र में अपना हुनर दिखाने का अवसर मिलेगा।
- पंचायत, वार्ड, प्रखंड एवं ज़िला स्तर तक खेल में प्रतिभाशाली युवाओं को हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स समेत अन्य खेलों में अपना हुनर दिखाने का अवसर मिलेगा।
- योजना के तहत आयोजित प्रतियोगिताओं में ज़िला एवं राज्यस्तर पर विजेताओं और उप-विजेताओं को प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित भी किया जाएगा।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में खेल की नर्सरी स्थापित की जाएंगी, ताकि झारखंड की खनिज के अतिरिक्त भी पहचान स्थापित हो सके। हर स्तर पर खेल का आयोजन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने Safe and Responsible Migration Initiative (SRMI) का किया शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

- 16 दिसंबर, 2021 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय स्थित सभागार में प्रवासी मज़दूरों के पलायन को सुरक्षित बनाने हेतु बनाई गई पॉलिसी Safe and Responsible Migration Initiative (SRMI) का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- वर्तमान में Safe and Responsible Migration Initiative (SRMI) पायलट प्रोजेक्ट के तहत दुमका, पश्चिमी सिंहभूम तथा गुमला के श्रमिकों के पलायन को ध्यान में रखकर नीति बनाई गई है।
- इन तीन ज़िलों से दिल्ली, केरल और लेह-लद्दाख इत्यादि जगहों में रोज़गार के लिये गए प्रवासी श्रमिकों का डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। इन सभी राज्यों से समन्वय स्थापित कर प्रवासी श्रमिकों के सामाजिक, आर्थिक और कानूनी हक सुनिश्चित किये जाएंगे।
- प्रवासी श्रमिकों का किसी भी प्रकार से शोषण न हो सके, इस निमित्त नियम बनाए गए हैं। शुरुआती दौर में इस पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद व्यवस्था के दायरे को और बड़ा बनाया जा सकेगा।
- इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने BOCW के अंतर्गत विवाह सहायता योजना, मातृत्व प्रसुविधा योजना, अंत्येष्टि सहायता योजना, झारखंड निर्माण कर्मकार मृत्यु/दुर्घटना सहायता योजना एवं मेधावी पुत्र-पुत्री छात्रवृत्ति सहायता योजनाओं का लाभ सभागार में उपस्थित लाभुकों के बीच वितरित किया।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर किसी प्रवासी श्रमिक की मृत्यु होती है तो राज्य सरकार उसके दिवंगत शरीर को वापस उसके घर लाने की व्यवस्था करेगी तथा अंत्येष्टि का पूरा खर्चा राज्य सरकार ही वहन करेगी। इसके लिये सभी ज़िलों में कॉरपस फंड की व्यवस्था की जा रही है।
- राज्य के प्रवासी मज़दूरों को संरक्षित करने के लिये सरकार द्वारा ई-श्रम पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल के तहत प्रवासी श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन किया जाता है, ताकि विपत्ति के समय राज्य सरकार उन्हें तत्काल मदद पहुँचा सके।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश इत्यादि राज्यों से रेस्क्यू कर लाई गई युवतियों एवं महिलाओं को टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रोज़गार देने का काम राज्य सरकार ने हाल के दिनों में किया है। 2 हज़ार नियुक्ति पत्र टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बाँटे गए थे, जिनमें 80% महिलाएँ थीं।

नोट :

ICJS अवार्ड में झारखंड पुलिस की CCTNS को देश में मिला तीसरा स्थान

चर्चा में क्यों ?

- 17 दिसंबर, 2021 को नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की ओर से नई दिल्ली में आयोजित दोदिवसीय (16-17 दिसंबर) इंटिग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (आईसीजेएस) अवार्ड कार्यक्रम में झारखंड पुलिस व तेलंगाना पुलिस को जॉइंट रूप से तीसरा स्थान मिला।

प्रमुख बिंदु

- यह पुरस्कार क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम (सीसीटीएनएस) के क्षेत्र में झारखंड पुलिस के बेहतर प्रदर्शन के लिये मिला है। हालाँकि, पहले स्थान पर मध्य प्रदेश और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र पुलिस रही।
- क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम (सीसीटीएनएस) से झारखंड पुलिस, कोर्ट व जेल एक स्क्रीन पर, एक क्लिक पर किसी भी क्रिमिनल की डिटेल एक मिनट में प्राप्त कर सकते हैं। यह व्यवस्था आम पब्लिक के लिये नहीं है।
- इससे राज्य के लगभग 592 पुलिस स्टेशन जुड़े हुए हैं। केवल आठ पुलिस स्टेशन में यह व्यवस्था नहीं है। जिन आठ पुलिस स्टेशन में सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट काम नहीं कर रहा है, वहाँ रेल-टेल के माध्यम से भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है।

उदयन माने बने पीजीटीआई ऑर्डर ऑफ मेरिट चौंपियन

चर्चा में क्यों ?

- 19 दिसंबर, 2021 को ओलंपियन उदयन माने ने पीजीटीआई की टाटा स्टील टूर चैंपियनशिप जीतते हुए 2020-21 सत्र के लिये पीजीटीआई ऑर्डरऑफ मेरिट खिताब हासिल किया।

प्रमुख बिंदु

- दो बार के एशियाई टूर विजेता राशिद खान इस चैंपियनशिप में उपविजेता रहे।
- यह चैंपियनशिप 16 से 19 दिसंबर, 2021 तक जमशेदपुर में बेलडीह और गोलमुरी गोल्फ कोर्स में आयोजित की गई थी।
- माने को 22,50,000 रुपए की पुरस्कार राशि मिली और उन्होंने सीजन की कमाई के आधार पर मेरिट सूची में करणदीप कोचर और चिक्कारंगप्पा को पीछे छोड़ दिया।
- गौरतलब है कि उदयन ने इससे पहले जमशेदपुर में 2019 टाटा स्टील टूर चैंपियनशिप भी जीती थी। उन्होंने 2020-21 सीजन के दौरान चार खिताब जीते हैं। यह उनका 12वाँ पीजीटीआई खिताब है।

स्कॉच पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

- 18 दिसंबर, 2021 को झारखंड के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह को नई दिल्ली में एक समारोह में स्कॉच फाउंडेशन द्वारा लोक सेवा के लिये स्कॉच पुरस्कार प्रदान किया गया।

प्रमुख बिंदु

- स्कॉच फाउंडेशन के समीर कोचर ने कहा कि अरुण कुमार सिंह द्वारा औद्योगिक विकास, वाणिज्यिक कर, पर्यटन, लोक निर्माण विभाग, कृषि, जल संसाधन, शहरी विकास, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के क्षेत्र में किये गए कार्यों के लिये उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है।
- कोविड की पहली लहर के दौरान पीडीएस और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन सहित खाद्य और नागरिक आपूर्ति में तथा कोविड की खतरनाक दूसरी लहर के दौरान स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग में इनका अनुकरणीय एवं पेशेवर संचालन विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा।

नोट :

- गौरतलब है कि स्कॉच अवार्ड्स को भारत का सर्वोच्च स्वतंत्र सम्मान माना जाता है और इसके प्राप्तकर्त्ताओं में बीस साल के इतिहास में नियामक, सचिव, केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री रहे हैं।

'उड़ान 2021' क्विज के विजेता बने जयकांतन आर

चर्चा में क्यों ?

- 19 दिसंबर, 2021 को सेल (SAIL) के प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित 'उड़ान: कॉर्पोरेट्स के लिये बिज़नेस लीडरशिप क्विज'के ग्रैंड फिनाले में TCS के जयकांतन आर ने प्रथम पुरस्कार जीता।

प्रमुख बिंदु

- इसका आयोजन सेल, एमटीआई (प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान) ने नेशनल एचआरडी नेटवर्क (एनएचआरडीएन), राँची चैप्टर के सहयोग से किया था।
- प्रतियोगिता का प्रारंभिक दौर 28 और 30 नवंबर, 2021 को, जोनल फाइनल 8, 9, 13 और 15 दिसंबर, 2021 को तथा नेशनल ग्रैंड फिनाले 19 दिसंबर की देर शाम को आयोजित किया गया था।
- 2011 से एमटीआई में आयोजित 'उड़ान'को इस साल 360 से अधिक प्रतिभागियों को नामांकित करने वाले लगभग 50 कॉर्पोरेट घरानों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। यह कार्यक्रम ऑनलाइन मोड में आयोजित किया गया था।
- सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और आईटी सक्षम सेवाओं, बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा, विनिर्माण, इस्पात और खनन क्षेत्रों आदि के संगठनों ने प्रश्नोत्तरी में भाग लिया।
- उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण क्षेत्रों में से प्रत्येक के शीर्ष छह स्कोरर ने जोनल फाइनल में एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा की।
- 'उड़ान 2021' के राष्ट्रीय विजेता टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) के जयकांतन आर ने 50,000 रुपए का नकद पुरस्कार प्राप्त किया, जिसे मेसर्स हेक्सागन द्वारा प्रायोजित किया गया था।
- नेशनल रनर-अप, अर्नेस्ट एंड यंग के आयुष अवस्थी ने 35,000 रुपए का नकद पुरस्कार जीता, जिसे मेसर्स एम डी इंडिया द्वारा प्रायोजित किया गया था।
- जोनल राउंड के विजेता और उपविजेता को क्रमश: 25,000 रुपए तथा 15,000 रुपए के नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

टाटा स्टील को मिला 'सुरक्षा और स्वास्थ्य मान्यता 2021'

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में टाटा स्टील को वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन (वर्ल्डस्टील) द्वारा 'व्यावसायिक स्वास्थ्य प्रबंधन'श्रेणी के तहत उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य उत्कृष्टता पहल के लिये मान्यता दी गई है।

प्रमुख बिंदु

- टाटा स्टील की ओर से नीरज सिन्हा, चीफ सेफ्टी, टाटा स्टील ने बेल्जियम के ब्रूसेल्स में सेफ्टी एंड हेल्थ कमेटी की बैठक के दौरान पुरस्कार प्राप्त किया।
- टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट (सेफ्टी हेल्थ एंड सस्टेनेबिलिटी) संजीव पॉल ने कहा कि टाटा स्टील में कई तकनीकी नवाचारों को लागू किया गया है और कार्यबल सुरक्षा एवं व्यावसायिक स्थिरता को आगे बढ़ाने के लिये अपनी डिजिटल परिवर्तन यात्रा का लाभ उठाया गया है। यह सम्मान टाटा स्टील को उत्कृष्टता को आगे बढ़ाने और भविष्य के लिये तैयार करने हेतु प्रेरित करेगा।
- पहल में कंपनी की निर्माण इकाइयों में तैनात दो प्रौद्योगिकी संचालित नवीन अवधारणाएँ 'पीओडी अवधारणा'और 'डिजिटल कोविड सुरक्षा ट्रैक'शामिल हैं। इन अनुप्रयोगों ने कोविड-19 जोखिमों को कम करके कार्यबल की सुरक्षा और व्यापार निरंतरता सुनिश्चित की तथा इन्हें कोविड इम्पैक्ट सेंटर के माध्यम से तेज़ी से लागू किया गया।

नोट :

- पीओडी (एक कार्यबल मॉडर्नाइजेशन अवधारणा) ने विशिष्ट कार्य करने के लिये स्व-निहित कौशल सेट के साथ ठेकेदारों सहित संचालन और रखरखाव कर्मियों वाले आत्मनिर्भर समूहों की शुरुआत की है।

विधानसभा में 2926.12 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पारित

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में झारखंड विधानसभा में भाजपा के बहिर्गमन के बावजूद 2926.12 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पारित किया गया। विपक्षी भाजपा ने झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) के प्रारंभिक परीक्षा परिणामों में गड़बड़ी के विरोध में सदन से वाकआउट किया।

प्रमुख बिंदु

- बजटीय आवंटन के अनुसार पेंशन मद में सर्वाधिक 620 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके बाद ऊर्जा विभाग के लिये 588 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य विभाग के लिये 518 करोड़ रुपए तथा जल संसाधन विभाग के लिये 231 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- इसी प्रकार गृह कारागार और आपदा प्रबंधन विभाग के लिये 208 करोड़ रुपए, उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग के लिये 172 करोड़ रुपए तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के लिये 188 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

ग्लोबल पीटर ड्रकर चैलेंज

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में बिजनेस स्कूल ''एक्सएलआरआई'' जमशेदपुर के छात्रों ने 'ग्लोबल पीटर ड्रकर चैलेंज'' अवार्ड जीता है।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि वियना में ड्रकर फोरम ने दुनिया भर के छात्रों, प्रबंधकों और उद्यमियों को अंतर्दृष्टि साझा करने के लिये आमंत्रित किया था, जो वैश्विक कार्यबल को आज की वीयूसीए दुनिया की गतिशील चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाएगा।
- इस प्रतियोगिता में कुल 49 देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। छात्र वर्ग के कुल तीन विजेताओं में एक्सएलआरआई के दो छात्र डॉ. नदीम अहमद और प्रभात कुझिककट शामिल थे। डॉ. नदीम और प्रभात क्रमश: बीएम और एचआरएम बैच 2021-23 के हैं।
- प्रभात ने कहा, 'एक्सएलआरआई सस्टेनेबिलिटी, एथिक्स और मानवीय सहानुभूति' पर ज़ोर देता है, जिससे उसे ड्रकर फोरम में भाग लेने वाले प्लेनरीज के साथ जुड़ने में मदद मिली।
- वहीं हेल्थकेयर टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट डॉ. नदीम अहमद ने स्वास्थ्य संबंधी बाधाओं को दूर करने का प्रयास कर रहे स्टार्टअप्स को सशक्त बनाने के उद्देश्य से 'कोरोना कंसल्ट' नामक एक क्रॉस-फंक्शनल प्रो-बोनो इनिशिएटिव की स्थापना की है ?
- विदित हो कि XLRI जेविअर स्कूल ऑफ मैनजमेंट, जमशेदपुर, भारत का सबसे पुराना बी-स्कूल है, जिसकी स्थापना 1949 में कुछ दूरदर्शी जेसुइट फादर्स द्वारा अर्थव्यवस्था और समाज में बड़े पैमाने पर बदलाव लाने के लिये की गई थी।

गरिमा परियोजना अंतर्गत डायन कुप्रथा मुक्त झारखंड के लिये कार्यशाला आयोजित

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में झारखंड स्टेट लाईवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी द्वारा डायन कुप्रथा मुक्त झारखंड के निर्माण के लिये आयोजित कार्यशाला में झारखंड के ग्रामीण विकास सचिव, डॉ. मनीष रंजन ने कहा कि गरिमा परियोजना के माध्यम से झारखंड को डायन कुप्रथा मुक्त बनाया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- डॉ. मनीष रंजन ने कहा कि गरिमा परियोजना के तहत वल्नरेबिलिटी मैपिंग एवं ग्राम संगठन के प्रशिक्षण के जरिये डायन कुप्रथा उन्मूलन को गति प्रदान किया जाएगा। जल्द ही जेंडर मंच बनाया जाएगा, जिससे डायन कुप्रथा जैसे अंधविश्वास एवं भेदभाव को दूर कर लोगों को जागरुक करने का काम किया जाएगा।

नोट :

- उन्होंने कहा कि गरिमा परियोजना के जरिये सखी मंडल की बहनों द्वारा नुक्कड़ नाटक के जरिये भी प्रभावित गाँवों में जागरुकता अभियान चलाया जाएगा एवं डायन कुप्रथा पीड़ितों की सुरक्षा व काउंसिलिंग की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही डायन कुप्रथा की पीड़ित महिलाओं के पुनर्वास पर भी काम किया जाएगा और उन्हें सशक्त आजीविका से जोड़ा जाएगा।
- शिक्षाविद् व यूजीसी वूमेंस सेंटर की प्रमुख डॉ. सुनीता रॉय ने कहा कि समाज को शिक्षित करने से ही डायन कुप्रथा का उन्मूलन संभव है। उन्होंने अपील की कि डायन प्रथा की पीड़ित महिलाओं को प्रशिक्षित करके ही सशक्त आजीविका से जोड़ा जा सकता है। ग्रामीण इलाके से ओझा गुणी प्रथा को खत्म करने के लिये शिक्षा के अलख जगाने की ज़रुरत है।
- उन्होंने समाज में लैंगिंक समानता एवं महिला सशक्तीकरण के लिये कार्य करने की ज़रूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि किन्नरों को भी विभिन्न जागरुकता अभियान में जोड़ने की ज़रुरत है ताकि उनके आजीविका की भी व्यवस्था हो।
- झालसा के संतोष कुमार ने बताया कि झालसा, राज्य में डायन कुप्रथा पीड़ितों को कानूनी मदद करने के लिये लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि हमें वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने की ज़रुरत है, जल्द ही झालसा के द्वारा स्कूलों में लीगल साक्षरता क्लब का गठन किया जा रहा है, जो डायन कुप्रथा उन्मूलन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
- नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ के वाइस चांसलर डॉ. केशव राव ने बच्चों को डायन कुप्रथा के बारे में जागरुक करने की ज़रूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सेंटर फॉर लीगल एंड प्रोग्राम के तहत डायन कुप्रथा के पीड़ितों को लगातार मदद उपलब्ध कराई जा रही है।
- सीआईपी के निदेशक डॉ. बासुदेब प्रसाद ने कहा कि गरिमा परियोजना के अंतर्गत सीआईपी मानसिक स्वास्थ्य एवं मनोचिकित्सीय सहयोग के लिये कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य काउंसिलिंग के लिये सीआईपी के 15 हेल्पलाइन नंबर दिन-रात कार्य कर रहे हैं।

बिरसा मुंडा संगीत और नृत्य महोत्सव

चर्चा में क्यों ?

- 25-26 दिसंबर, 2021 को झारखंडवासियों के बीच कला और संस्कृति के महत्त्व को बढ़ावा देने के लिये, एमिटी विश्वविद्यालय, झारखंड द्वारा पंडित चंद्र कुमार मलिक मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से दोदिवसीय बिरसा मुंडा संगीत और नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर राज्यपाल ने पद्मश्री से सम्मानित मधु मंसूरी हसमुख, कलाकार नीलेश मलिक, पंडित राजकुमार झा, प्रो. मोहम्मद, मंजूषा रंजन, सचिन कुमार, गार्गी मलखानी, श्रीजीत चटर्जी और अशोक दास को सम्मानित किया।
- इसके साथ ही राज्यपाल ने एमिटी विश्वविद्यालय, झारखंड के शैक्षणिक उपलब्धि पुरस्कार 2021 संकाय सदस्य डॉ. जयता चटोपाध्याय और डॉ. सुमीरा मलिक को प्रदान किया।

एकीकृत कृषि क्लस्टर

चर्चा में क्यों ?

- 24 दिसंबर, 2021 को केंद्रीय ग्रामीण विकास सचिव एनएन सिन्हा ने राज्य की राजधानी राँची में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत एकीकृत कृषि क्लस्टर पहल का अनावरण किया।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि इस एकीकृत कृषि क्लस्टर पहल का अनावरण झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (जेएसएलपीएस) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में किया गया, जिसमें विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।

नोट :

- कार्यशाला को संबोधित करते हुए सिन्हा ने राज्य में सखी मंडलों के माध्यम से आजीविका सशक्तिकरण के लिये किये जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने अन्य राज्यों के प्रतिनिधियों से कहा कि वे अपने राज्यों में आजीविका संसाधन केंद्र और दीदी बगिया योजना सहित अन्य गतिविधियों को लागू करें।
- उन्होंने कहा कि दूर-दराज के गाँवों के अंतिम परिवारों को मज़बूत आजीविका से जोड़ने के लिये राज्य स्तर से सभी विभागों के साथ समन्वय स्थापित करें, ताकि लाभार्थियों को सभी योजनाओं का लाभ एकीकृत तरीके से मिल सके।
- एकीकृत कृषि क्लस्टर के शुभारंभ पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सचिव ने सभी एनआरईटीपी राज्यों को सूक्ष्म नियोजन को प्रभावी तरीके से करने की सलाह दी, ताकि ग्रामीण समुदाय इस पहल से लाभान्वित हो सके।
- उन्होंने कहा कि सखी मंडलों के संगठनों को क्लस्टर स्तर के महासंघ को और मज़बूत करना चाहिये, ताकि आने वाले दिनों में यह एक मॉडल के रूप में विकसित हो सके और इससे आजीविका एवं सामाजिक समावेश को गति मिल सके। उन्होंने सभी राज्यों से प्रोड्यूसर इंटरप्राइज के काम में तेज़ी लाने को कहा।
- राज्य ग्रामीण विकास विभाग के सचिव डॉ. मनीष रंजन ने कहा कि ड्रिप सिंचाई से महिलाओं की आय दोगुनी हो गई है और लोगों की आय बहुफसलों तथा पशुपालन से बढ़ रही है। प्रशिक्षण के माध्यम से विभिन्न संवर्गों की क्षमता निर्माण, पीवीटीजी परिवारों के वित्तीय समावेशन को सशक्त बनाना, विभिन्न कौशल गतिविधियों में महिलाओं को शामिल करना राज्य की प्राथमिकता है, जिससे ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा मिलेगा।
- भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव चरणजीत सिंह ने एकीकृत कृषि क्लस्टर के बारे में बताते हुए कहा कि इस पहल का उद्देश्य किसानों को 'अंत से अंत तक समाधान' प्रदान करना है। उन्होंने झारखंड के पलाश ब्रांड और आदिवा ब्रांड की प्रशंसा की तथा अन्य राज्यों को झारखंड की इस पहल से सीखने को कहा।

सुशासन सूचकांक, 2021 में झारखंड

चर्चा में क्यों ?

- 25 दिसंबर, 2021 को सुशासन दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा सुशासन सूचकांक जारी किया गया, जिसमें ग्रुप 'बी' में झारखंड को चतुर्थ रैंक प्राप्त हुई है।

प्रमुख बिंदु

- जीजीआई-2021 में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को चार श्रेणियों- समूह ए, समूह बी, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश में बाँटकर रैंकिंग दी गई है। जीजीआई-2021 तैयार करने के लिये 10 क्षेत्रों के 58 संकेतकों पर विचार किया गया है।
- झारखंड ने सुशासन सूचकांक की समग्र रैंकिंग में 4.763 स्कोर के साथ ग्रुप 'बी' में चतुर्थ रैंक प्राप्त किया है, वहीं मध्य प्रदेश को ग्रुप 'बी' में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। गुजरात ने ग्रुप 'ए' में प्रथम रैंक प्राप्त की है।
- झारखंड ने पिछले सूचकांक (2019) की तुलना में अपने स्कोर में 12.6 प्रतिशत की वृद्धि की है। पिछली बार इसका स्कोर 4.23 था, जो अब बढ़कर 4.76 हो गया है।
- झारखंड ने मूलत: कृषि और संबद्ध क्षेत्र, सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र, सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगिता क्षेत्र सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगिता क्षेत्र तथा समाज कल्याण एवं विकास क्षेत्र में सुधार किया है।
- सुशासन सूचकांक 10 क्षेत्रों पर आधारित है, जिसमें झारखंड की रैंकिंग तथा स्कोर निम्नलिखित हैं-

क्षेत्र	झारखंड की रैंकिंग	स्कोर
1. कृषि और संबद्ध क्षेत्र	तृतीय	0.509
2. वाणिज्य एवं उद्योग क्षेत्र	6वीं	0.629
3. मानव संसाधन विकास क्षेत्र	6वीं	0.417
4. सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र	द्वितीय	0.481

नोट :

5. सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगिता क्षेत्र	तृतीय	0.636
6. आर्थिक शासन क्षेत्र	तृतीय	0.442
7. समाज कल्याण एवं विकास	5वीं	0.516
8. न्यायिक एवं सार्वजनिक सुरक्षा	चतुर्थ	0.287
9. पर्यावरण क्षेत्र	तृतीय	0.335
10. नागरिक केंद्रित शासन	8वीं	0.510

मुख्यमंत्री आमंत्रण राज्यस्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता-2021 का समापन

चर्चा में क्यों ?

- 27 दिसंबर, 2021 को मुख्यमंत्री आमंत्रण (बालक एवं बालिका) राज्यस्तरीय प्रतियोगिता-2021 का समापन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री आमंत्रण (बालक एवं बालिका) राज्यस्तरीय प्रतियोगिता-2021 के फाइनल में पूर्वी सिंहभूम की बालिका वर्ग ने रामगढ़ की बालिका वर्ग को 4-2 से हराया, वहीं बालक वर्ग में भी पूर्वी सिंहभूम की टीम ने राँची की टीम को 3-2 से हराकर ट्रॉफी पर कब्ज़ा जमाया।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्यस्तरीय इस प्रतियोगिता में लगभग डेढ़ लाख बच्चों ने हिस्सा लिया है। राज्य में यह पहला मौका है, जब इतनी बड़ी संख्या में हमारे बच्चे ऐसे खेल आयोजन से जुड़े हैं।
- झारखंड के कई खिलाड़ियों ने अपने हुनर का लोहा मनवाते हुए देश और दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। यहाँ के कई खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में देश के लिये कप्तानी भी की है। यहां के खिलाड़ियों के हुनर और क्षमता को प्लेटफॉर्म देकर उनका मार्ग प्रशस्त करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है।
- इस प्रतियोगिता का आयोजन विगत एक माह पूर्व से ही किया गया था। इससे खिलाड़ियों में उत्साह जगा है और कई खिलाड़ी उभर कर सामने भी आए हैं। राज्य में अन्य खेलों के साथ फुटबॉल खेल एवं खिलाड़ियों को बढ़ावा देने हेतु निरंतर प्रयास किया जा रहा है।
- इस मौके पर मुख्यमंत्री ने फाइनल मैच के बालक तथा बालिका वर्ग की विनर टीम तथा रनर टीम के प्रतिभागियों को मेडल, नगद पुरस्कार राशि तथा खेल किट इत्यादि देकर सम्मानित किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रतियोगिता के सफल आयोजन में अपनी महती भूमिका निभाने वाले टेक्निकल सपोर्ट पर्सन को भी सम्मानित किया।

नीति आयोग स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में झारखंड

चर्चा में क्यों ?

- 27 दिसंबर, 2021 को सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग ने 2019-20 के लिये अपने स्वास्थ्य सूचकांक का चौथा संस्करण जारी किया, जिसमें समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन के आधार पर राज्यों की रैंकिंग की गई। इसमें बड़े राज्यों में समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन के मामले में झारखंड 13वें स्थान पर है, वहीं केरल शीर्ष पर है।

प्रमुख बिंदु

- रिपोर्ट को तीन भागों में बाँटा गया था- बड़े राज्य, छोटे राज्य और केंद्रशासित प्रदेश। छोटे राज्यों में मिज़ोरम सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य रहा जबकि नागालैंड सबसे नीचे रहा।
- नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रशासित प्रदेशों में चंडीगढ़ शीर्ष पर है, उसके बाद दादरा और नगर हवेली दूसरे नंबर पर तथा दिल्ली तीसरे नंबर पर है।
- बड़े राज्यों में समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन के मामले में झारखंड 47.55 स्कोर के साथ 19 राज्यों में 13वें स्थान पर है। वहीं केरल 82.20 स्कोर के साथ पहले, तमिलनाडु 72.42 स्कोर के साथ दुसरे एवं तेलंगाना 69.96 स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर हैं।

नोट :

- नीति आयोग का स्वास्थ्य सूचकांक एक भारित समग्र स्कोर है, जिसमें स्वास्थ्य प्रदर्शन के प्रमुख पहलुओं को शामिल करते हुए 24 संकेतक हैं।

'बिरसा हरित ग्राम योजना'पर आधारित प्रशिक्षण पुस्तिका का विमोचन

चर्चा में क्यों ?

- 28 दिसंबर, 2021 को झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग के सचिव डॉ. मनीष रंजन ने मनरेगा के अंतर्गत महत्त्वाकांक्षी योजना 'बिरसा हरित ग्राम योजना'पर आधारित प्रशिक्षण पुस्तिका का विमोचन किया।

प्रमुख बिंदु

- डॉ. मनीष रंजन ने कहा कि यह पुस्तिका 'बिरसा हरित ग्राम योजना'के लाभुकों एवं बागवानी सखी/मित्र, महिला मेट एवं मनरेगा कर्मियों हेतु मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि मनरेगा के अंतर्गत बागवानी योजना के निरंतर विस्तार से न केवल आजीविका को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी बल्कि झारखंड राज्य को और भी हरा-भरा बनाने एवं फल की सर्वाधिक उत्पादकता वाले राज्यों की श्रेणी में लाने में मदद मिलेगी।
- इस अवसर पर मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी. ने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बिरसा हरित ग्राम योजना के उद्देश्य की पूर्ति हेतु बिरसा हरित ग्राम योजना के ऊपर यह प्रशिक्षण पुस्तिका तैयार की गई है।
- इस पुस्तिका में बागवानी योजना के चयन से लेकर इसके देखभाल एवं फसलों की बीमारी की पहचान एवं इसके उपचार हेतु महत्त्वपूर्ण दिशा-निर्देश का उल्लेख किया गया है।
- उन्होंने कहा कि यह प्रशिक्षण पुस्तिका बिरसा हरित ग्राम योजना के लाभुकों, बागवानी सखी/मित्र, महिला मेट एवं मनरेगा कर्मियों के प्रशिक्षण हेतु अत्यंत उपयोगी साबित होगी।
- मनरेगा आयुक्त ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार सृजन करने एवं खेती आधारित आजीविका को संबल प्रदान करने हेतु मनरेगा अंतर्गत 'बिरसा हरित ग्राम योजना'का क्रियान्वयन विगत कुछ वर्षों से किया जा रहा है।
- बागवानी योजना से न केवल गरीब परिवारों की आय के अतिरिक्त स्रोत का सृजन हुआ है बल्कि उनकी बंजर खाली पड़ी ज़मीनों को उपजाऊ बनाने एवं इसकी उपयोगिता बढ़ाने में भी मनरेगा की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। साथ ही बागवानी के अंदर अन्य कई प्रकार की फसलों एवं सब्ज़ियों की अंत: खेती (Intercropping) से लाभुक अपनी आजीविका को और भी सुदृढ़ बनाने की ओर अग्रसर है।

सरकार की दूसरी वर्षगाँठ के अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों को दी कई सौगातें

चर्चा में क्यों ?

- 29 दिसंबर, 2021 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य सरकार की दूसरी वर्षगाँठ के अवसर पर मोरहाबादी मैदान में आयोजित राज्यस्तरीय समारोह में 17,222.02 करोड़ रुपए की 1454 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए राज्यवासियों को कई सौगातें दीं।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राज्य के छात्र-छात्राओं के लिये स्टूडेंट्स क्रेडिटकार्ड योजना लागू करने की घोषणा की, उन्होंने कहा कि जल्द ही राज्य के विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने मोटरसाइकिल या स्कूटर में पेट्रोल भराने वाले राशन कार्डधारियों को 25 रुपए प्रति लीटर की दर से राशि उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। यह व्यवस्था अगले वर्ष 26 जनवरी से लागू की जाएगी। एक गरीब परिवार प्रतिमाह 10 लीटर पेट्रोल तक यह राशि प्राप्त कर सकता है।
- मुख्यमंत्री ने झारखंड आंदोलनकारी के आश्रितों को नौकरियों में 5 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की घोषणा की।
- मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के विदेशों में पढ़ाई के लिये चलाई जा रही शत-प्रतिशत छात्रवृत्ति योजना का दायरा बढ़ाते हुए इसमें अन्य वर्ग के होनहार विद्यार्थियों को भी जोड़ा जाएगा।

नोट :

- मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के गरीब विद्यार्थियों को भी बेहतर और गुणवत्तायुक्त शिक्षा मिले, इसके लिये राज्य सरकार ने अगले सेशन से कई सरकारी विद्यालयों में निजी स्कूलों की तर्ज पर पढ़ाई शुरू करने का निर्णय लिया है। यहाँ विद्यार्थियों को शिक्षा से संबंधित सभी ज़रूरी एवं मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध होंगी।
- समारोह में मुख्यमंत्री ने समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना सह किसान पाठशाला का शुभारंभ किया। पहले चरण में 17 किसान पाठशाला खोले जाएंगे, जबकि आने वाले तीन सालों में इसकी संख्या को बढ़ाकर एक सौ करने की योजना है।
- समारोह में मुख्यमंत्री ने महिलाओं को एनिमिया और बच्चों को कुपोषण की समस्या से निजात दिलाने के संदर्भ में एक हज़ार दिनों का विशेष समर अभियान शुरू करने का ऐलान किया।
- राज्य में 12वीं पास विद्यार्थियों को आईटी की ट्रेनिंग देने के लिये श्रम विभाग और एचसीएल टेक्नोलॉजी के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया। इसके तहत यहाँ के इंटर पास विद्यार्थियों को एचसीएल कंपनी के द्वारा प्लेसमेंट लिंक्ड ट्रेनिंग प्रोगाम से जोड़ा जाएगा और प्लेसमेंट की भी व्यवस्था की जाएगी।
- वनोत्पादों को बाज़ार उपलब्ध कराने की दिशा में वन विभाग, कल्याण विभाग और इंडियन स्कूल ऑफ बिज़नेस के बीच त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। इससे यहाँ के वन उपज को व्यावसायिक बाज़ार उपलब्ध कराने में सहूलियत होगी।
- मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राज्य के पत्रकारों के लिये पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने की घोषणा की। इस योजना के तहत उन्हें पाँच लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलेगा। मीडियाकर्मियों के साथ उनके परिजनों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा।
- मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 17,222.02 करोड़ रुपए की 1454 योजनाओं का उद्घाटन-शिलान्यास किया। इसमें 2965.22 करोड़ रुपए की 20 राज्यस्तरीय और 10770.88 करोड़ रुपए की अन्य 1014 योजनाओं का शिलान्यास किया।
- शिलान्यास की जाने वाली योजनाओं की कुल लागत 13,736.1 करोड़ रुपए है। वहीं, 1287.51 करोड़ रुपए की लागत से 20 राज्यस्तरीय और 2198.41 करोड़ रुपए की लागत से 400 योजनाओं का उद्घाटन हुआ। इसके अलावा 1493.38 रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण लाभुकों के बीच किया गया।

IIT-ISM और डसॉल्ट ने खनन और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिये MoU पर हस्ताक्षर किये

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में डसॉल्ट सिस्टम्स (यूरोनेक्स्ट पेरिस) ने भारत में एक विश्व-स्तरीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिये IIT(ISM) धनबाद के टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब 'टेक्समिन' (टेक्नोलॉजी इनोवेशन इन एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग) फाउंडेशन के साथ भागीदारी की है जो खनन और संबद्ध उद्योगों के लिये विशिष्ट प्रौद्योगिकी सहायता प्रदान करेगा और भविष्य के लिये कार्यबल तैयार करेगा।

प्रमुख बिंदु

- एक प्रौद्योगिकी और समाधान भागीदार के रूप में, डसॉल्ट सिस्टम्स अपने 3DEXPERIENCE प्लेटफॉर्म के माध्यम से औद्योगिक और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करने के लिये भूवैज्ञानिक मॉडलिंग और खदान इंजीनियरिंग से लेकर कार्यबल और उत्पादन शेड्यूलिंग, आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन, पोर्टफोलियो अनुकूलन और संयंत्र डिज़ाइन तक पूर्ण पिट-टू-पोर्ट अनुकूलन के साथ अनुभवात्मक शिक्षा प्रदान करेगा।
- यह साझेदारी छात्रों और पेशेवरों को सीखने के अनूठे अवसरों के साथ सशक्त बनाएगी और उन्हें इस तेज गति वाले उद्योग के लिये तैयार करेगी।
- कोर्स और कार्यक्रम 3DEXPERIENCE® प्लेटफॉर्म पर आभासी दुनिया को मिलाकर तैयार किए जाएंगे जो पूर्ण डिजिटल परिवर्तन की क्षमताओं को खोलने व स्थायी खनन और धातुओं की नई वास्तविकता का अनुभव अनुभव करने के लिये एक स्रोत प्रदान करता है।

नोट :